प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

25.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

''मुख्य समाचार''

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–सरकार की शर्तें नहीं मानने वाली पनबिजली परियोजनाओं को लिया जाएगा वापिस।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा–कोरोना काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने को सरकार प्रयासरत्त।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में गलत तथ्य पेश करने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के जलाश्यों में जलस्तर में आई कमी–केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को एडवाइजारी की जारी।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि केन्द्रीय उपक्रमों एनएचपीसी व एसजेवीएन को बिजली परियोजनाएं दी गई हैं और उनके लिए राज्य सरकार की शर्तों को नहीं माना जा रहा है। इसके दृष्टिगत इन्हें वापिस लिया जाएगा और इन परियोजनाओं के लिए दी गई अतिरिक्त जमीन भी उनसे वापस ली जाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैय्यर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी का बैरास्यूल प्रोजेक्ट व चमेरा–एक प्रोजेक्ट 40 साल पुराना हो चुका है और कायदे से इसे सरकार को लौटाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होगा कि 12 फीसदी मुफ्त रॉयल्टी में हमेशा के लिए उनके पास परियोजनाएं रहेंगी।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन सभी मसलों पर सरकार कानूनी राय लेते हुए आगे बढ़ रही है। विधायक हंसराज के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि कोई भी परियोजना 40 साल के लिए ही दी जाएगी और 12, 18 व 30 फीसदी बिजली रॉयल्टी की शर्त भी रहेगी।

विधायक आर.एस बाली के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा मेडिकल कालेज को बने 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां सीनियर रजिस्ट्रार के पद सृजित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ये पद सृजित करेगी। उन्होंने टांडा मेडिकल कालेज व अस्पताल में नई लिफ्ट लगाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी मेडिकल कालेज व अस्पताल अपने स्तर पर न्यूनतम यूजर चार्जिज़ लगा सकते हैं ताकि अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मेडिकल कालेज स्वायत संस्थान हैं और यदि वे यूजर चार्जिज लगाते हैं तो सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। विधायक अजय सोलंकी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहन मेडिकल कालेज जहां मौजूदा समय में है, वहां इसका विस्तार संभव नहीं है। ऐसे में सरकार ने इसे दूसरी जगह स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सौ 61 बीघा जमीन का चयन भी कर लिया गया है और यह मामला केंद्रीय वन व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, इस भवन पर अभी तक सौ करोड़ 88 लाख रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं और इसे पूरा करने के लिए 3 सौ 70 करोड़ रुपए और चाहिए।

विधायक लोकेंद्र कुमार, रणधीर शर्मा और बिक्रम सिंह के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में पशुपालकों और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही गोबर खरीद योजना के तहत बीते दो वर्षों में एक सौ 5 पशुपालकों से कुल 4 सौ 21 क्विंटल कम्पोस्ट खाद की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने प्रति किलो तीन रुपये की दर से भुगतान किया, जिससे कुल एक लाख 26

हज़ार 3 सौ रुपये की राशि किसानों को प्राप्त हुई। चंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में किसानों से कम्पोस्ट खाद की खरीद की गई।

कटौती प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवा में एडजेस्ट करने का प्रयास करेगी जिन्होंने कोरोना काल में सेवाएं दी हैं और जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई है। विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित पहले चरण के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अगले सात माह में बनकर तैयार हो जाएंगे और इनका कार्य अंतिम चरण में है। धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार जल्द ही 11 नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अधिसूचित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में अपनी तैनाती वाली जगहों पर ज्वाइन नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चमियाणा और टांडा मैडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू करेगी। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला में अगले तीन माह में पैटस्कैन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सहारा योजना के तहत अभी तक लाभार्थियों को एक सौ 39 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत सरकार को निजी अस्पतालों का अभी 3 सौ 44 करोड़ रुपए देना शेष है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में गलत तथ्य रखने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नालागढ़ में खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सदन में गलत तथ्य पेश किए गए जबकि खनन के लिए ज़मीन कांग्रेस सरकारों के समय में दी गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन को इस तरीके से गुमराह करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को भी राजनीति न करने की नसीहत और नियमावली के अनुसार अपना कार्य करने को कहा।

सिकंदर कुमार

हिमाचल प्रदेश में जलाशयों का जल स्तर काफी गिर गया है और इसका असर जल विद्युत उत्पादन व फसलों की सिंचाई पर पड़ सकता है। राज्यसभा में सांसद डॉ. सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि राज्य के जलाशयों में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा 13 मार्च 2025 को जारी बुलेटिन के अनुसार हिमाचल के तीन प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज कम हो गई है राज भूषण चौधरी ने बताया कि इस वर्ष जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति सामान्य से 33 फीसदी कम दर्ज की गई है, जिससे जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कम वर्षा और बर्फबारी के कारण केंद्रीय जल आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एडवाइजरी जारी की है और राज्य सरकार से इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिट्टा माफिया और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 27 मार्च को शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी कार्यकर्ता व अन्य लोग इस दौरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार के अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कांग्रेस सरकार ने जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है जिससे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं।

इंदु गोस्वामी

केन्द्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में बैंगलुरू की कम्पनी के सहयोग से फूड सप्लीमेंट एक्टोसाइट लॉन्च किया है जो रेडिओथेरेपी की प्रक्रिया से गुजरने वाले कैंसर रोगियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। राज्य सभा सांसद इंदु गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। जितेन्द्र सिंह ने बताया कि एक्टोसाइट टैबलेट के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसके लाभों को अंतिम रूप देने के लिए क्लीनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं।

''मुख्य समाचार एक बार फिर''

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—सरकार की शर्ते नहीं मानने वाली पनबिजली परियोजनाओं को लिया जाएगा वापिस।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा—कोरोना काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने को सरकार प्रयासरत्त।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खनन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में गलत तथ्य पेश करने का लगाया आरोप।
- प्रदेश के जलाश्यों में जलस्तर में आई कमी—केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को एडवाइजारी की जारी।